

सेवा में

एन०एस०एमल०ब्याल,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

जिलाधिकारी,  
देहरादून।

राज्य विभाग

देहरादून: दिनांक: 17 मार्च, 2006

विषय: मॉ गंगे प्रसिद्धे एजुकेशनल फाउण्डेशन सोसायटी को फार्मैसी पाठ्यक्रम के संचालन हेतु तहसील विकासनगर के ग्राम मझौन में कुल 2.5 एकड़ अतिरिक्त भूमि कय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-229/12ए-19(2005-08)/डी०एल०आर०सी० दिनांक 2 जनवरी, 2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मॉ गंगे प्रसिद्धे एजुकेशनल फाउण्डेशन सोसायटी को फार्मैसी पाठ्यक्रम के संचालन हेतु उत्तरांचल (उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(III) के अन्तर्गत तहसील विकासनगर के ग्राम मझौन में कुल 2.5 एकड़ अतिरिक्त भूमि कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

- 1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेंगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- 3- क्रेता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की

गई हैं। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसी स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि छय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अरांकगणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- स्थापित किये जाने वाले संस्थान में उत्तरांचल के निवासियों को 70 प्रतिशत शेजगार/सेवायोजन उपलब्ध कराया जायेगा।

7- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शरान उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त करदी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एन0एस0नपलब्याल)  
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, धौली।
- 3- सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तरांचल शासन।
- 4- सचिव, मां मंगे प्रतिष्ठे एजुकेशनल फाउण्डेशन सोसायटी, शास्त्रीनगर, स्ट्रीट नं0-4 हर्द्वार रोड, देहरादून।
- 5- निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तरांचल सचिवालय।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)  
अपर सचिव।